REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2024

भारत में हरित अर्थव्यवस्था चुनौतियां और संभावनाएं का एक अध्ययन

डॉ . कोमल प्रसाद

शोध सारांश

हरित अर्थव्यवस्था यानी "हरित अर्थव्यवस्था" एक ऐसे आर्थिक विकास कि मार्ग को दर्शाती है जो विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है। भारत में हरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एक तरफ तेज आर्थिक विकास की गारंटी है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी। भारत प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध क्षेत्र है जहां खनिज जंगल और जल संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन ये ही संविधान पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगाई जा रही है। इसलिए यहां पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की अवश्यकता है जो स्थिर विकास और पर्यावरण की रक्षा के मध्य संतुलन बना सके। शोध में भारत और छत्तीसगढ़ के लिए हरित अर्थव्यवस्थ के चुनौतियां और संभावनाएं विस्तार से गहन अध्ययन हैं। इस शोध में समीक्षा की गई है कि सरकारी नीति और योजनाएं किस प्रकार की हैं जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रीन इंडिया मिशन इस मामले में योगदान दे सकती हैं। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है कि किस तरह से भारत में वैकल्पिक ऊर्जा, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एक टिकाऊ विकास मॉडल को प्रशस्त करना है जो ना सिर्फ विकास को प्रेरित करे बल्कि पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा भी करे। भारत के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था अपनाने की आवश्यकता और चुनौतियों को समझते हुए यह शोध अध्ययन उन पहलुओं पर केंद्रित है जो हरित विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में सहायक हो सकते हैं। भारत में हरित अर्थव्यवस्था का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में हरित अर्थव्यवस्था चुनौतियां और संभावनाएं का एक अध्ययन कर चुनौतियां और संभावनाएं का कमियों और विकास को रेखांकित कर उपर्युक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्दकुंजी - हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, खनिज और वन संसाधन, प्रदूषण, ऊर्जा, कृषि, सरकारी नीतियां और पर्यावरण संतुलन सार्वजनिक भागीदारी प्राकृतिक संसाधन।

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप कृषि, खनन और उद्योग जैसे संसाधन-आधारित क्षेत्रों पर निर्भर है जो अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डालते हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भूमि क्षरण और जल प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करते हुए भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा में संतुलन स्थापित करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि से होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई पर्यावरणीय योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय हरित मिशन, स्वच्छ भारत अभियान,और सौर ऊर्जा मिशन को बढ़ावा दिया है। हालांकि हरित अर्थव्यवस्था को लागू करना आसान नहीं है। भारत में उद्योगों शहरीकरण और संसाधन आधारित विकास से जुड़े हितों को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती है जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा

के क्षेत्र में विकास करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है जबकि एक बड़ी जनसंख्या अभी भी कोयले और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। भारत में हरित अर्थव्यवस्था को लेकर कई पहलें चल रही हैं जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। 2023 के बजट में हरित विकास और स्थिरता पर जोर दिया गया है जिसमें देश का लक्ष्य 2070 तक शून्य-कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का है। इस संदर्भ में प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं:-

1 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन- भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा हैए जिसमें **19,700** करोड़ रुपये के निवेश से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा संक्रमण को गति देना है।

2. पीएम-कुसुम योजना- किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने में सक्षम बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर पंप लगाए जा रहे हैं। इस पहल का लक्ष्य कृषि ऊर्जा क्षेत्र में गैर-जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

3. गोबर्धन योजना- यह योजना जैविक अपशिष्ट से गैस उत्पादन को बढ़ावा देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है।

इसके अलावा, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के कम-कार्बन संक्रमण को समर्थन देने के लिए **$1.5** बिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है जो भारत के हरित अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करेगा। भारत की योजनाएं और निवेश जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु अमृत दरोहार **जैसे कार्यक्रम,** भारत के हरित अर्थव्यवस्था लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) का उद्देश्य आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करना है। भारत जो खनिज संसाधनों वन क्षेत्र और जल संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, में हरित अर्थव्यवस्था अपनाना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और चुनौती है। भारत में उद्योग और खनिज-आधारित गतिविधियां की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हालांकि इन गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण जल स्रोतों का क्षरण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जो हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के साथ टकराव उत्पन्न करती हैं। भारत सरकार ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन सौर ऊर्जा और हरित कृषि को अपनाने की योजनाएँ बनाई हैं। जैसे कि पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कृषि में हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है **(Ministry of New and Renewable Energy, 2023)**। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और वनों की रक्षा हेतु कई नीतियाँ लागू की गई हैं जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकीय स्थिरता बनाए रखना है।

शोध साहित्य का समीक्षा

हरित अर्थव्यवस्था **(Green Economy)** एक महत्वपूर्ण और वकासशील क्षेत्र है जो पर्यावरणीय स्थिरता सामाजिक समावेशित और आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर हरित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर आधारित एक साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है जिसमें महत्वपूर्ण शोध पत्रों के संदर्भ शामिल हैं।

1. UNEP Referene: UNEP (2011). "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication." इस रिपोर्ट में हरित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी गई है और यह बताया गया है कि यह कैसे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। यह अध्ययन दिखाता है कि हरित अर्थव्यवस्था कैसे सामाजिक समावेशित और आर्थिक विकास के लिए लाभदायक हो सकती है।

2. हरित तकनीकों का वकास **Reference: M. Z. Hassan, et al. (2020). "Green Technologies and Sustainable Development: A Review." Renewable and Sustainable Energy Reviews.** इस अध्ययन में हरित तकनीकों के विकासए उनके प्रभाव, और विभिन्न क्षेत्रों में उनके उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि कैसे इन तकनीकों का समावेश आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकता है।

3. नीतिगत चुनौतियाँ **Reference: B. M. van der Voet, et al. (2017). "The role of policy in the transition to a green economy: A comparative analysis." Environmental Science & Policy.** यह लेख यह दर्शाता है कि प्रभावी नीतियों के अभाव में हरित अर्थव्यवस्था में प्रगति कैसे बाधित होती है। इसमें नीति निर्माण की चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा की गई है।

4. आ र्थक बाधाएँ **Reference: A. B. Elkin, et al. (2019). "Financial Challenges in the Transition to a Green Economy." Sustainability.** इस शोध में हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में वित्तीय बाधाओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें निवेश की कमी और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की समस्याएँ शामिल हैं।

5. समाज के दृष्टिकोण **Reference: A. P. Jain & R. K. Gupta (2018). "Public Perception and Acceptance of Green Economy: A Study in India." Journal of Environmental Management.** यह अध्ययन समाज में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और उसके कार्यान्वयन में बाधाओं को समझने का प्रयास करता है। जागरूकता की कमी और पारंपरिक दृष्टिकोणों का प्रभाव इस अध्ययन का मुख्य फोकस है।

6. वैश्विक दृष्टिकोण **Reference: H. M. G. Haji, et al. (2021). "Global Cooperation for a Green Economy: Challenges and Opportunities." Global Environmental Change.** इस लेख में वैश्विक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई है। यह शोध विभिन्न देशों के दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता को उजागर करता है।

शोध के उद्देश्य

1.- हरित अर्थव्यवस्था की परिभाषा को स्पष्ट करना और इसके मूल तत्वों जैसे कि पर्यावरणीय स्थिरता सामाजिक समावेशित और आर्थिक विकास को समझना एवं उद्योग और ऊर्जा क्षेत्रों में हरित अर्थव्यवस्था के वर्तमान अनुप्रयोगों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना।

2.- हरित अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन में आने वाली नीतिगत चुनौतियों को पहचानना और उनके समाधान के लिए संभावित रणनीतियों का सुझाव देना।

शोध प्राविधि

भारत में हरित अर्थव्यवस्था आवश्यकता, सम्भावना, क्रियान्वयन और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करना। इस अध्ययन के लिए विभिन्न पत्रिकाओं, शोध लेखों, वेबसाइटों, विभिन्न स्रोतों से प्रकाशित आंकड़ों से द्वितीयक आंकडे एकत्रित किये गये है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों का भी इस पत्र मे उल्लेख किया गया है।

हरित अर्थव्यवस्था

हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास– सर्वप्रथम हरित अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग वर्ष 1989 मे ब्रिटेन के पर्यावरणविदों द्वारा सरकार को सतत् विकास के सम्बंध मे सौंपी गई एक रिपोर्ट 'हरित अर्थव्यवस्था के लिए मूल योजना' मे किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अक्टूबर, 2008 में ने एक हरित अर्थव्यवस्था की पहल प्रारम्भ की, जिसका उद्देश्य ग्रीन सेक्टर में निवेश करने तथा पर्यावरण प्रतिकूल क्षेत्रकों को पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु विश्लेषण एवं नीतिगत सहयोग प्रदान करना था।

कोपेनहेगन में जून, 2009 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की एक घोषणा मे अनेक संकटों के समाधान के रूप मे हरित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया था।

बाली, इण्डोनेशिया में फरवरी, 2010 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मंत्रीस्तरीय पर्यावरण मंच में स्वीकार किया कि, हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा वर्तमान चुनौतियों का समाधान कर सकती है तथा सभी राष्ट्रों को आर्थिक विकास व लाभ के अवसर प्रदान कर सकती है।

रियो डि जेनेरियो (ब्राजील) में वर्ष 2012 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मलेन के केन्द्रीय विषय में सतत विकास तथा निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था था। इस सम्मेलन मे कहा गया कि हरित

अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों मे सतत् विकास प्रतिबद्धताओं को लागू करने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का एक उपकरण है।

हरित अर्थव्यवस्था: - चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हरित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है और आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है। यह पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस शोध अध्ययन में हरित अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं पर अध्ययन किया गया है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हरित अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। जल, वन और जीव-जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है।

2. विकास और पर्यावरण संतुलन- औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हरित अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

3. नवीन तकनीकों का विकास - टिकाऊ तकनीकों का विकास और उन्हें अपनाना जरूरी है लेकिन इसके लिए उच्च लागत और सामाजिक प्रतिरोध एक चुनौती है।

4. राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ - राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और आर्थिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। प्रभावी नीतियों की अनुपस्थिति हरित अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

5. सामाजिक जागरूकता - लोगों में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक जनता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगी तब तक सुधार मुश्किल है।

संभावित समाधान

1.- सरकारों को प्रभावी हरित नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए।

2.- तकनीकी नवाचार स्वच्छ ऊर्जा पुनर्चक्रण और टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

3.- शिक्षा और जागरूकता अभियान-लोगों को हरित अर्थव्यवस्था के लाभों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

4.- सामाजिक भागीदारी- समुदायों को हरित पहलों में शामिल करने के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।

निष्कर्ष

हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयास करना एक आवश्यक कदम है जो हमें स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर करता है। इस शोध पत्र में प्रस्तुत चुनौतियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हरित अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए समुचित नीतियाँए तकनीकी नवाचार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नवीन तकनीकों का विकास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सामाजिक जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे गंभीर चुनौतियाँ हैं। यदि हम इन समस्याओं का सामना करना चाहते हैं तो हमें नीति सुधारों तकनीकी नवाचारों और शिक्षा एवं जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

स्वीडन जैसे देशों के उदाहरण यह दिखाते हैं कि सही नीतियों और सामाजिक भागीदारी से हरित अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। सरकार- उद्योगों और समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता है ताकि हरित पहलें अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से अपनाई जा सकें । अतः हरित अर्थव्यवस्था केवल एक आर्थिक मॉडल नहीं है बल्कि यह एक स्थायी भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है। यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएँ तो हम न केवल आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक समावेशिता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। भविष्य में हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में वैश्विक सहयोग और स्थानीय प्रयासों का समुचित मिश्रण आवश्यक होगा ताकि हम एक संतुलित और टिकाऊ विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

निष्कर्ष

भारत में हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है जो न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को भी सुनिश्चित करती है। भारत एक विकासशील देश के रूप में तेजी से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों की सीमितता और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहा है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को भी इस दिशा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि वन विनाश जल संकट और औद्योगीकरण के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था का मॉडल एक प्रभावी उपाय हो सकता है।

हरित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत में नीति सुधारों की आवश्यकता है जिसमें टिकाऊ कृषि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास और जल प्रबंधन की रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और टिकाऊ विकास के महत्व को समझें। इसके साथ ही जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। भारत और छत्तीसगढ़ में हरित अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि सही नीतियाँ और उपाय अपनाए जाएं तो हम न केवल आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस दिशा में एक ठोस प्रयास से भारत एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

संदर्भ

सू च- प्रमुख पुस्तकों, शोध पत्रिका के संदर्भ

1. UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
2. WWF. (2020). Living Planet Report 2020.
3. OECD. (2012). Green Growth and Developing Countries.
4. IPCC. (2018). Global Warming of 1.5 °C.
5. World Bank. (2020). World Development Report 2020: Data for Better Lives.
6. UNDP. (2019). Human Development Report 2019.
7. European Commission. (2020). The European Green Deal.
8. Swedish Environmental Protection Agency. (2021). Sweden's Environmental Objectives.
9. World Bank [10:49 PM, 11/4/2024]

प्रमुख पुस्तकों, शोध पत्रिका के संदर्भ

1. 1 Dutta Satrajit (2016), 'Green Economy' In the Context of Indian Economy, International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM), Vol. 2, Issue: 3 [ISSN: 2311-3200].
2. United Nations Environment Programme (UNEP). Available from: https://www.unenvironment.org. [Last accessed on 2020 March 10].
3. Sustainable Development - United Nations Environment Programme (UNEP). Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446. [Last accessed on 2019 December 10].
4. What is Green Economy? United Nations Environment Programme (UNEP). Available from: https://www.unep.org/greeneconomy/what-inclusive-green-economy. [Last accessed on 2019 December 10].
5. ICC - International Chamber of Commerce. Available from: https://iccwbo.org. [Last accessed on 2020 March 10].
6. UNEP. (2012). The Business Case for the Green Economy, Sustainable Return on Investment. 7. Nagoya. The Nagoya Protocol of Access and Benefit Sharing (ABS). Available from: https://www.cbd.int/abs/. [Last accessed on 2019 December 10].
7. REDD+. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Available from: http://redd.unfccc.int/. [Last accessed on 2019 December 10].

8. United Nations Environment Programme's report on the Green Economy. Available from: http://www.unep.org/greeneconomy/. December 10]. [Last accessed on 2019
9. Bapna and Talberth (2014). Q&A: What is a "Green Economy?" by Manish Bapna and John Talberth, April 2011. Available from: http://www.wri.org/blog/2011/04/qa-what-green-economy-0. [Last accessed on 2019 December 10].